



सैंटरल बैंक डजिटिल करेंसी

प्रलिस के लयि :

सैंटरल बैंक डजिटिल करेंसी, भारतीय रजिख बैंक (RBI), करपिटोकंरेंसी, फरिट मुद्रा, अनौपचारकि अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा ।

मेन्स के लयि:

सैंटरल बैंक डजिटिल करेंसी, इसका महत्त्व और चुनौतयिँ ।

[स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ

हाल ही में [भारतीय रजिख बैंक \(RBI\)](#) के गवरनर ने सीमा पार भुगतान की दक्षता में सुधार के लयि [सैंटरल बैंक डजिटिल करेंसी \(CBDC\)](#) या ई-रुपए की क्षमता पर प्रकाश डाला है ।

- RBI अधकि बैंकोँ, शहरों, वविधि उपयोग के मामलोँ और व्यापक उपयोगकर्ताओं को शामिल करने के लयि धीरे-धीरे अपने CBDC पायलटों का वसितार कर रहा है ।
- RBI ने नवंबर 2022 में थोक और दसिंबर 2022 में खुदरा क्षेत्र में डजिटिल रुपये के लयि पायलट लॉन्च कयिा ।

सैंटरल बैंक डजिटिल करेंसी (CBDC):

- परचिय:
 - CBDC कागज़ी मुद्रा का डजिटिल रूप है और कसिी भी नयामक संस्था द्वारा संचालति नहीं होने वाली [करपिटोकंरेंसी](#) के वपिरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी तथा समर्थति वैध मुद्रा है ।
 - यह [फरिट मुद्रा](#) के समान है और फरिट मुद्रा के साथ वन टू वन वनिमिय करने में सक्षम है ।
 - फरिट मुद्रा राष्ट्रिय मुद्रा है जो कसिी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चाँदी की कीमत पर नहीं आँकी जाती है ।
 - [ब्लॉकचेन](#) द्वारा समर्थति वॉलेट का उपयोग करके डजिटिल फरिट मुद्रा या CBDC का लेन-देन कयिा जा सकता है ।
 - हालाँकि CBDC की अवधारणा सीधे तौर पर [बटिकॉइन](#) से प्रेरति थी, यह वकिेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं एवं करपिटो परसिंपत्तयिँ से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और जनिमें 'कानूनी नविदि'(लीगल टेंडर) स्थति का अभाव है ।
- उद्देश्य:
 - इसका मुख्य उद्देश्य जोखमिँ को कम करना और भौतिक मुद्रा को संभालने, फटे पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की लागत, परविहन, बीमा तथा रसद में लागत को कम करना है ।
 - यह लोगोँ को धन हस्तांतरण के साधन के रूप में करपिटोकंरेंसी से भी दूर रखेगा ।
- वैश्वकि रुझान:
 - बहामास, वर्ष 2020 में अपना राष्ट्रव्यापी CBDC - सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था रही है ।
 - नाइजीरया वर्ष 2020 में eNaira शुरू करने वाला दूसरा देश है ।
 - अप्रैल 2020 में चीन डजिटिल मुद्रा e-CNY का संचालन करने वाला दुनया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया ।

डिजिटल रुपया

- ◆ भारतीय रुपये का एक डिजिटल संस्करण।
 - ◆ ई-रुपये के रूप में भी जाना जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)।
 - ◆ निजी स्वामित्व वाली क्रिप्टो के विपरीत एक केंद्रीय स्वामित्व वाली डिजिटल मुद्रा।
 - ◆ ऑफलाइन कार्यक्षमता प्रस्तावित-कोई भी इंटरनेट के बिना लेनदेन कर सकता है।
- दस देशों ने CBDC की शुरुआत कर दी है जिनमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में बहामियन सैंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जमैका का JAM&DEX।

लाभ

- ◆ वित्तीय प्रणाली में न्यूनतम व्यवधान।
- ◆ **जोखिम से मुक्त:** क्रिप्टो के साथ देखे गए जोखिमों के विपरीत यह लोगों को डिजिटल रूप में मुद्रा में लेनदेन का अनुभव प्रदान करता है,
- ◆ **यथोचित अनामिता:** भौतिक नकदी के समान छोटे मूल्य के लेनदेन के लिये यथोचित अनामिता प्रदान करता है

ई-रुपये का क्रियान्वयन

- ◆ **CBDC-खुदरा मोड:** यह संभावित रूप से सभी के उपयोग के लिये उपलब्ध होगा जिसे CBDC-R भी कहा जाता है।
 - * यह नागरिकों के लिये डिजिटल भुगतान के सुरक्षित साधन की पेशकश कर सकता है।
 - * यह संभवतः नकदी के समान, टोकन-आधारित हो सकता है।



- ◆ **CBDC-थोक मोड:** चुनिंदा वित्तीय निकायों तक सीमित पहुंच के लिये, जिसे CBDC-W भी कहा जाता है।
 - * निपटान प्रणालियों को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य।
 - * यह खाता-आधारित हो सकता है।

मुद्दे

- ◆ साइबर सुरक्षा
- ◆ गोपनीयता और डेटा उपयोग का मुद्दा
- ◆ डिजिटल अंतराल
- ◆ अन्य बाजार के प्रतिस्पर्धियों जैसे वीजा, मास्टरकार्ड आदि की तुलना में अप्रतिस्पर्धी कदम।

CBDC का महत्त्व

- सीमा पार लेन-देन:
 - CBDC में अद्वितीय विशेषताएँ हैं जो सीमा पार लेन-देन में क्रांति ला सकती हैं।
 - **CBDC** की त्वरित निपटान सुविधा एक मुख्य लाभ है, जो सीमा पार से भुगतान को सस्ता, दुरुत और अधिक सुरक्षित बनाती है।
 - तेज़, सस्ती, पारदर्शी एवं समावेशी सीमा पार भुगतान सेवाएँ विश्व भर में व्यक्तियों और अर्थव्यवस्थाओं के लिये पर्याप्त लाभ ला सकती हैं। ये सुधार वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय समावेशन का समर्थन कर सकते हैं।
- पारंपरिक और नवीन:
 - CBDC मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।
 - आभासी और वास्तविक मुद्रा के हित में **CBDC** की परिकल्पना:
 - क्रिप्टोकॉर्सेसी जैसे डिजिटल रूपों की सुविधा और सुरक्षा
 - पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का वनियमिति, आरक्षण-समर्थन धन परसिंचरण शामिल है।
- वित्तीय समावेशन:
 - बेहतर कर एवं नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु असंगठित अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाने के लिये कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के संबंध में भी CBDC के बढ़ते उपयोग की तलाश की जा सकती है।

- यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

पूरे भारत में CBDC को अपनाने हेतु चुनौतियाँ:

- **गोपनीयता से संबद्ध मुद्दे:**
 - केंद्रीय बैंक संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं से लेन-देन के संबंध में बड़ी मात्रा में डेटा को संगृहीत करेगा जो व्यक्ति की नजिता/ गोपनीयता के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
 - इसके गंभीर नहितार्थ हैं क्योंकि डिजिटल मुद्राएँ उपयोगकर्ताओं को नकदी में लेनदेन द्वारा प्रदान की जाने वाली गोपनीयता और गुमनामी के स्तर की पेशकश नहीं करेंगी।
 - साख का समझौता इसमें प्रमुख मुद्दा है।
- **बैंकों की मध्यस्थता समाप्त करना:**
 - यदि पर्याप्त रूप से **बड़े और व्यापक CBDC** में बदलाव आता है तो यह बैंक की साख मध्यस्थता में धन वापस करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि ई-कैश लोकप्रिय हो जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) उस राशि की कोई सीमा नहीं रखता है जैसा मोबाइल वॉलेट में संगृहीत किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में छोटे बैंक नमिन-लागत वाली जमा राशि को भी बनाए रखने के लिये संघर्ष कर सकते हैं।
- **अन्य जोखिम:**
 - **प्रौद्योगिकी का तीव्र अपरचलन CBDC पारस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा** उत्पन्न कर सकता है जिसके लिये उन्नयन की उच्च लागत की आवश्यकता होगी।
 - मध्यस्थों के परिचालन जोखिम के रूप में कर्मचारियों को CBDCs के अनुकूल कार्य करने के लिये फरि से प्रशिक्षित और तैयार करना होगा।
 - **साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम** में वृद्धि, भेद्यता परीक्षण और फायरवॉल की सुरक्षा की लागत।
 - CBDC के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक पर परिचालन बोझ और लागत।

आगे की राह

- केंद्रीय बैंकों को **CBDC के अनुसंधान, विकास और संचालन** के लिये अपने प्रयास जारी रखने चाहिये। CBDC का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों व अन्य हतिधारकों के साथ सहयोग आवश्यक है।
- विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों और वित्तीय प्राधिकरणों को CBDC पहल पर सहयोग करना चाहिये। सीमा पार से भुगतान में स्वाभाविक रूप से कई क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं, ऐसे में वनियामक, सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।
- सुरक्षा और गोपनीयता CBDC के लिये प्राथमिक होना चाहिये। हैकर्स और धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने के लिये ठोस साइबर सुरक्षा उपाय होने चाहिये। साथ ही, उपयोगकर्ता की गोपनीयता व डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2023)

1. अमेरिकी डॉलर या एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. प्रणाली का उपयोग कयि बनिा डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है।
2. कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामगि प्रतबंधि, जैसे कइ इसके वयय के समय-ढाँचे के साथ वतिरति की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनो
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)